कानपुर, मंगलवार, 31 मार्च, 2026
वर्षः 03, अंकः 81, पृष्ठः 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

स्वराज इंडिया

साप्ताहिक समाचार पत्र

इनसाइड खून के कारोबार में लापरवाही, 7 ब्लड बैंक सील...>Pg09

सपनों की कीमत 'जिस्म' से चुकाई...>Pg03

मूल्यः ₹

एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आईएक्स-1523 के कॉकपिट में धुआं, इमरजेंसी लैंडिंग से बची 148 जिंदगियां

36 हजार फुट की ऊंचाई पर 'दहशत'

स्वराज इंडिया ब्यूरो

लखनऊ। आसमान में 36 हजार फुट की ऊंचाई पर उड़ते विमान में जब कॉकपिट से धुआं उठने की आशंका हुई, तो कुछ पलों के लिए 148 यात्रियों की सांसें थम गईं। बागडोगरा से दिल्ली जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आईएक्स-1523 में सोमवार शाम पैदा हुआ यह खतरा किसी बड़े हादसे में बदल सकता था, लेकिन पायलट की सूझबूझ और तत्परता ने सभी यात्रियों को सुरक्षित जमीन पर लौटा दिया।

फ्लाइट बिहार पार कर उत्तर प्रदेश के आसमान में थी, तभी कॉकपिट के एवियोनिक पैनलों से धुआं महसूस हुआ। यह संकेत बेहद गंभीर था, क्योंकि उड़ान के दौरान कॉकपिट में धुआं आग या तकनीकी खराबी का संकेत हो सकता है। स्थिति भांपते ही पायलट ने बिना देर किए इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू किया और नजदीकी सुरक्षित एयरपोर्ट लखनऊ की ओर विमान को डायवर्ट करने का फैसला लिया।

इस दौरान विमान में मौजूद यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क उपलब्ध कराए गए। अचानक हुए इस घटनाक्रम से यात्रियों में दहशत फैल गई, कई लोग प्रार्थना करने लगे तो कुछ ने अपने परिजनों को अंतिम संदेश तक भेज दिए। हर सेकंड भारी लग रहा था। उधर, लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया। रनवे पर फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम और सुरक्षा एजेंसियां तैनात कर दी गईं। शाम 5:17 बजे विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की और विमान रुकते ही राहत की लहर दौड़ गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

घटना के बाद विमान को जांच के लिए एयरपोर्ट पर खड़ा कर दिया गया है। पिछले 15 घंटे से तकनीकी और सुरक्षा टीमें धुएं के कारणों की जांच कर रही हैं। शुरुआती जांच में कोई बड़ी खराबी सामने नहीं आई है, लेकिन एवियोनिक सिस्टम में मामूली गड़बड़ी भी बड़े खतरे का कारण बन सकती है, इसलिए विस्तृत जांच जारी है।

एयरलाइन ने यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की। कुछ को अन्य उड़ानों से दिल्ली भेजा गया, जबकि अन्य को होटल में ठहराया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की स्थिति में पायलट का त्वरित निर्णय ही जीवन और मृत्यु के बीच फर्क तय करता है और इस बार यह फैसला यात्रियों की जिंदगी बचाने वाला साबित हुआ। 36 हजार फुट पर कुछ मिनटों की दहशत ने यह साफ कर दिया कि हवाई यात्रा में तकनीकी सतर्कता और पायलट की त्वरित निर्णय क्षमता कितनी अहम होती है। इस घटना में जहां एक संभावित हादसा टल गया, वहीं यह भी याद दिला गया कि आसमान में हर सेकंड सुरक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता

- आसमान में अचानक संकट, ऑक्सीजन मास्क के बीच दहशत का माहौल
- पायलट की सूझबूझ से लखनऊ में सुरक्षित उतरा विमान, 15 घंटे से जांच जारी

- 36 हजार फीट की ऊंचाई पर कॉकपिट में धुआं दिखा
- फ्लाइट में कुल 148 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे
- ऑक्सीजन मास्क जारी कर इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू किया गया
- लखनऊ एयरपोर्ट पर 5:17 बजे सुरक्षित लैंडिंग
- 15 घंटे से तकनीकी जांच जारी
- यात्रियों के लिए वैकल्पिक उड़ान और ठहरने की व्यवस्था

क्यों खतरनाक है कॉकपिट में धुआं?

- कॉकपिट विमान का कंट्रोल सेंटर होता है, यहां धुआं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल कर सकता है
- एवियोनिक सिस्टम में खराबी नेविगेशन और कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है
- धुआं आग में बदल सकता है, जो हवा में सबसे बड़ा खतरा होता है

हाल के वर्षों में ऐसे मामलेः टाइमलाइन

2024 - दिल्ली-श्रीनगर फ्लाइट अलर्ट
- उड़ान के दौरान केबिन में जलने की गंध आने पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।

2023 - मुंबई से दुबई उड़ान में धुआं
- टेकऑफ के कुछ देर बाद कॉकपिट में धुआं महसूस हुआ, विमान को वापस मुंबई लौटाया गया।

2022 - इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी
- इंजन से जुड़ी समस्या के चलते बीच उड़ान में ही विमान को डायवर्ट करना पड़ा।

2021 - स्पाइसजेट विमान में धुआं
- केबिन में धुआं भरने की शिकायत के बाद आपात लैंडिंग कराई गई, सभी यात्री सुरक्षित रहे।

शीतला अष्टमी पर नालंदा मंदिर में भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत

आस्था की भीड़ बनी काल

स्वराज इंडिया ब्यूरो

नालंदा। शीतला अष्टमी के पावन अवसर पर आस्था का सैलाब अचानक मातम में तब्दील हो गया। नालंदा जिले के एक शीतला माता मंदिर में मंगलवार सुबह मची भगदड़ ने 9 जिंदगियों को निगल लिया। जिन हाथों में पूजा की थालियां थीं, वही हाथ कुछ ही पलों में अपनों को ढूंढते-ढूंढते बेबस हो गए। मंदिर परिसर में बिछी लाशें और चारों ओर गूंजती चीख-पुकार ने हर किसी को भीतर तक झकझोर दिया।

बताया जा रहा है कि चैत्र माह के अंतिम मंगलवार को शीतला माता के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे थे। मंदिर परिसर में लगे मेले ने भीड़ को और अधिक बढ़ा दिया। सुबह के समय जैसे ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ा, व्यवस्था चरमराने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भीड़ को नियंत्रित करने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। संकरी जगह, अव्यवस्थित कतारें और जल्द दर्शन की होड़ ने हालात को विस्फोटक बना दिया। देखते ही देखते धक्का-मुक्की शुरू हुई और कुछ ही क्षणों में यह भगदड़ में बदल गई। महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आए। जमीन पर गिरे लोगों को उठने का मौका तक नहीं मिला और भीड़ उन्हें कुचलती चली गई। इस भयावह मंजर में 8 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक पुरुष ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

हादसे के बाद मंदिर परिसर श्मशान सा सन्नाटा और करुण क्रंदन से भर गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। कोई अपनी मां को पुकार रहा था तो कोई बहन को। मृतकों में अब तक रीता देवी (50) और रेखा देवी (45) की पहचान हो सकी है, जबकि अन्य की शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है। घटना में कई श्रद्धालु घायल भी हुए हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए मंदिर और मेले को तत्काल बंद करा दिया। राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

घटना पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। राज्य सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 6 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से 2 लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजा और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है।

- बेकाबू भीड़ में कुचल गईं 8 महिलाएं, एक ने अस्पताल में तोड़ा दम
- मातम में बदला पर्व का उल्लास, परिजनों के करुण क्रंदन से गूंजा इलाका
- अव्यवस्था पर उठे सवाल, केंद्र-राज्य ने 8 लाख तक मुआवजे का ऐलान

भ्रष्टाचार की बुनियाद पर एल्डिको का एवॉक टावर, ग्राहकों से बड़ा धोखा !

- » चोरी की बिजली से खड़ा 13 मंजिला टावर, केस्को की रेड में कनेक्शन कटा
- » अव्यवस्थाओं का अंबार, सुविधाएं नदारद, फिर भी वसूली जारी
- » करोड़ों खर्च कर घर खरीदने वाले ग्राहक परेशान

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर।आईआईटी के पीछे स्थित जवाहरपुरम में विकसित एल्डिको टाउनशिप एक बार फिर सवालों के घेरे में है। स्वराज इंडिया की जमीनी पड़ताल में सामने आया है कि यहां टाउनशिप के नाम पर भारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ है। करोड़ों रुपये खर्च कर विला और फ्लैट खरीदने वाले ग्राहक अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

- ●नालियां जाम, जलभराव की समस्या
- ●सड़कों पर बजरी फैली, हादसों का खतरा
- ●स्ट्रीट लाइट व्यवस्था भी संदिग्ध

चोरी की बिजली से खड़ा हुआ टावर

एल्डिको द्वारा विकसित 13 मंजिला ÷एवॉक टावर÷ गंभीर आरोपों के केंद्र में है। जानकारी के अनुसार कंपनी ने पूरे प्रोजेक्ट के लिए घरेलू बिजली का लगभग 1600 चङ्क का सिंगल प्वाइंट कनेक्शन लिया, लेकिन उसी से व्यावसायिक निर्माण कार्य कराए गए।दिसंबर में केस्को की रेड के दौरान बिजली चोरी पकड़ी गई, जिसके बाद एवॉक टावर का कनेक्शन काट दिया गया। इसके बावजूद मौके पर अब भी संदिग्ध तरीके से बिजली उपयोग के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जेनरेटर के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में स्ट्रीट लाइट से केबिल जोड़कर बिजली ली जा रही है।

एवॉक टावर में करीब 60 फ्लैट हैं, जहां 2 क्काय की कीमत लगभग 70 लाख और 3 क्काय की कीमत 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। इसके बावजूद यहां मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है।

स्ट्रीट लाइट से जुड़ी अवैध केबल

मेंटीनेंस के नाम पर सिर्फ वसूली

स्थानीय निवासी अधिवक्ता मनीष पांडेय , संदीप शुक्ला और अनिल कनोडिया सहित कई अन्य के आरोप हैं कि टाउनशिप प्रबंधन मेंटीनेंस के नाम पर मोटी रकम वसूल रहा है, लेकिन सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिजली भी कमर्शियल दरों पर दी जा रही है, जिससे लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

विला भी हो रहे जर्जर

टाउनशिप में बने कई विला की हालत भी खराब हो चुकी है। बाहर से आकर्षक दिखने वाले मकानों के अंदर प्लास्टर गिर रहा है, दीवारों में सीलन है और निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन की गुणवत्ता (उसर मिट्टी) के कारण निर्माण कमजोर साबित हो रहा है।

प्रबंधन खामोश, जवाब देने से बच रहा

पूरे मामले में एल्डिको प्रबंधन की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। कंपनी के एमडी श्रीकांत झझोडिया से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। स्थानीय स्तर पर भी कोई जिम्मेदार अधिकारी सामने नहीं आया। जवाहरपुरम जैसी बड़ी टाउनशिप में इस तरह की अनियमितताएं कई सवाल खड़े करती हैं। क्या निर्माण के समय मानकों की अनदेखी की गई? क्या प्रशासनिक स्तर पर निगरानी में चूक हुई? और सबसे बड़ा सवाल–क्या ग्राहकों को उनका हक मिलेगा?टाउनशिप के नाम पर बड़े-बड़े वादे कर ग्राहकों से मोटी रकम वसूलने वाली कंपनियां अगर बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पा रहीं, तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सुनियोजित शोषण का मामला प्रतीत होता है। अब जरूरत है कि संबंधित विभाग इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे, ताकि उपभोक्ताओं को न्याय मिल सके।

कानपुर किडनी कांडः तीन अस्पतालों पर छापे से खुला अंगों के काले कारोबार का जाल

सपनों की कीमत ‘जिस्म’ से चुकाई

- 60 लाख का सौदा, हाथ में चंद लाख, एमबीए छात्र समेत कई युवकों को बनाया शिकार
- वार्डबॉय बना रैकेट का मास्टरमाइंड, शहर के तीन बड़े अस्पतालों में रेड से मचा हड़कंप

मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर में उजागर हुआ किडनी रैकेट अब और भी भयावह तस्वीर पेश कर रहा है। यह केवल दलालों या कुछ डॉक्टरों का खेल नहीं, बल्कि अस्पतालों तक फैला एक संगठित नेटवर्क है, जहां इंसानियत को खुलेआम नीलाम किया जा रहा था। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में तीन प्रमुख अस्पतालों में छापेमारी के बाद इस पूरे सिंडीकेट के तार और गहरे होते नजर आ रहे हैं।

जांच के दौरान जिन तीन अस्पतालों में प्रमुख रूप से छापेमारी की गई, उनमें मेड लाइफ हॉस्पिटल, कल्याणपुर, आहूजा हॉस्पिटल, रावतपुर, प्रिया हॉस्पिटल, पनकी रोड हैं। इन अस्पतालों से मिले सुरागों ने साफ कर दिया कि अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का खेल संगठित तरीके से चल रहा था। आईसीयू में संदिग्ध मरीजों की मौजूदगी और ट्रांसप्लांट के बाद मरीजों को अलग-अलग जगह शिफ्ट करना इस नेटवर्क की सोची-समझी रणनीति थी।

छापेमारी के दौरान कल्याणपुर स्थित एक अपार्टमेंट और अस्पतालों के आईसीयू से डोनर और रिसीवर दोनों मिले। यह संकेत देता है कि ऑपरेशन के बाद मरीजों को ट्रैक से हटाने के लिए लगातार लोकेशन बदली जाती थी। मामला उजागर होने के बाद अस्पताल संचालकों ने भी मरीजों को इधर-उधर शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। इस कांड की जड़ में दो अहम केस सामने आए हैं। जिनमें समस्तीपुर (बिहार) का एमबीए छात्र जिसने 9 लाख में सौदा किया और उसे मिले सिर्फ 5 लाख। इसी क्रम में उत्तराखंड के एक युवक को 60 लाख का लालच दिया गया। जबकि उसके हाथ में आए सिर्फ 9.5 लाख। जब दोनों ने बकाया रकम के लिए दबाव बनाया, तो दलालों और अस्पतालों की मिलीभगत सामने आने लगी।

कब-कब पकड़े गए ऐसे रैकेट

2016 दिल्ली-गुड़गांव में अंतरराष्ट्रीय किडनी रैकेट

2018 मुंबई में फर्जी ट्रांसप्लांट केस

2020 नोएडा में निजी अस्पताल का खुलासा

2022 कोलकाता में गरीबों को फंसाने वाला गिरोह पकड़ा गया

2024 जयपुर में मेडिकल स्टाफ की मिलीभगत उजागर

2026 कानपुर में तीन अस्पतालों से जुड़ा बड़ा नेटवर्क सामने आया

- तीन अस्पतालों मेड लाइफ, आहूजा और प्रिया हॉस्पिटल में रेड
- आईसीयू में मिले डोनर और रिसीवर
- 60 लाख के सौदे में डोनर को मिला सिर्फ 9.5 लाख
- एमबीए छात्र को 9 लाख में सौदा, मिला केवल 5 लाख
- वार्डबॉय बना गिरोह का सरगना
- फर्जी रिश्तेदारी दिखाकर ट्रांसप्लांट को वैध बनाया गया

वार्डबॉय से ‘डॉक्टर’ बना सरगना

पुलिस के मुताबिक इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड शिवम अग्रवाल उर्फ ‘काना’ बताया जा रहा है, जो असल में एक वार्डबॉय था। लेकिन वह खुद को डॉक्टर बताकर लोगों को भरोसे में लेता और फिर उन्हें इस खतरनाक सौदे में धकेल देता। उसकी कार्यप्रणाली बेहद सुनियोजित थी। गरीब और जरूरतमंद युवकों को टारगेट करना और उनके फर्जी दस्तावेज बनाने के बाद डोनर को ‘रिश्तेदार’ दिखा कर ट्रांसप्लांट को वैध रूप देना। जांच में सामने आया है कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लखनऊ और दिल्ली से डॉक्टरों की टीम बुलाई जाती थी। इससे साफ है कि यह नेटवर्क सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि कई शहरों में फैला हुआ था।

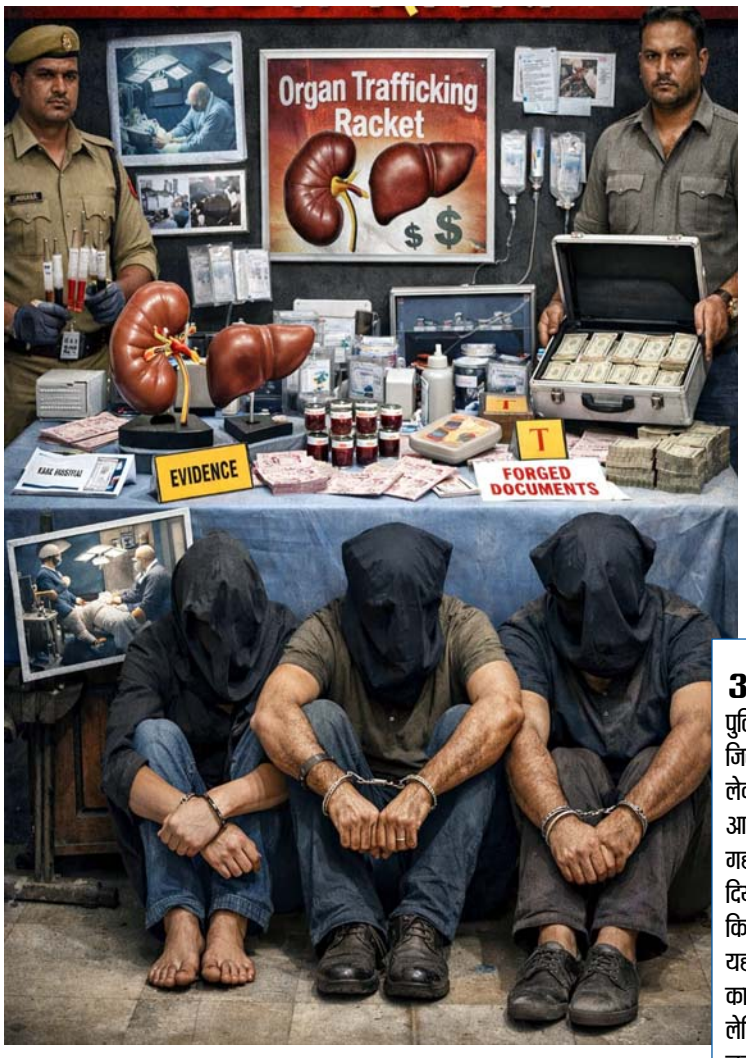

अस्पतालों की भूमिका कितनी गंभीर?

- अस्पतालों के बिना संभव नहीं ऐसा रैकेट
- आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर का इस्तेमाल
- फर्जी दस्तावेजों को ‘वैध’ बनाने में मदद

क्यों बनते हैं छात्र और गरीब शिकार?

- शिक्षा और इलाज का बढ़ता खर्च
- तत्काल पैसे की जरूरत
- जागरूकता की कमी
- दलालों के झूठे वादे

अब क्या करेगा सिस्टम?

- अस्पतालों की सख्त निगरानी
- ऑर्गन ट्रांसप्लांट सिस्टम का डिजिटलीकरण
- दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई
- डोनर सुरक्षा के लिए नए नियम

अस्पताल संचालक हिरासत में

पुलिस ने अब तक 6 अस्पतालों में छापेमारी की। जिसमें तीन अस्पताल संचालकों को हिरासत में लेकर डोनर और रिसीवर दोनों की पहचान की। आहूजा हॉस्पिटल से जुड़े डॉक्टरों और दलालों से गहन पूछताछ जारी है। पुलिस कमिश्नर ने संकेत दिया है कि जल्द ही पूरे सिंडीकेट का बड़ा खुलासा किया जाएगा। कानपुर का यह कांड एक बार फिर यह साबित करता है कि जब लालच और मजबूरी का टकराव होता है, तो इंसानियत हार जाती है। लेकिन तीन अस्पतालों में पड़ी रेड ने यह उम्मीद जरूर जगाई है कि इस बार यह नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त होगा और दोषियों को सजा मिलेगी।

नगर निगम का 2026-27 का मूल बजट पेश

33 अरब 59 करोड़ का वित्तीय खाका तैयार

आय में बढ़ोतरी के साथ 901.12 करोड़ का संभावित अवशेष संपत्ति कर व वित्त आयोग अनुदान में इजाफा

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नगर निगम का मूल बजट तैयार कर कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 146 के तहत तैयार इस बजट में दिसंबर 2025 तक के वास्तविक आय-व्यय आंकड़ों को आधार बनाया गया है।

मेयर प्रमिला पांडे ने बताया कि नगर निगम द्वारा प्रस्तुत बजट के अनुसार कुल प्रस्तावित आय 2459.32 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसमें 899.99 करोड़ रुपये के प्रारंभिक अवशेष को जोड़कर कुल बजट आकार 3359.31 करोड़ रुपये पहुंचता है। इसके सापेक्ष कुल प्रस्तावित व्यय 2458.18 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसके बाद 901.12 करोड़ रुपये का संभावित अवशेष रहने का अनुमान है।

नामांतरण शुल्क में बड़ी कटौती

शासन के निर्देशों के अनुसार शुल्क को एकमुश्त किए जाने से आय में गिरावट आई है। इसे 25.00 करोड़ से घटाकर मात्र 5.00 करोड़ रुपये किया गया है।

निष्प्रयोज्य भंडार बिक्री में कमी

इस मद में आय न होने के चलते 3.00 करोड़ से घटाकर 1.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अनुदानों से मजबूत होगी आय

राज्य वित्त आयोग अनुदान

750.00 करोड़ से बढ़ाकर 900.00 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

16वां वित्त आयोग

15वें वित्त आयोग के स्थान पर 16वें वित्त आयोग के तहत 500.00 करोड़ रुपये का प्रावधान।

अवस्थापना एवं आवास विकास मद- लंबित अनुदान मिलने की संभावना के चलते 55.00 करोड़ से बढ़ाकर 130.00 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

सीएसआर फंड में वृद्धि

50.00 लाख से बढ़ाकर 2.50 करोड़ रुपये किया गया।

वर्षा जल निकासी पर फोकस

वित्तीय वर्ष 2026-27 में वर्षा जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 31.00 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना जताई गई है, जो शहरी जलभराव की समस्या से निपटने में अहम भूमिका निभाएगा।

संतुलित बजट का दावा

नगर निगम प्रशासन का दावा है कि यह बजट आय और व्यय के बीच संतुलन बनाते हुए तैयार किया गया है। कर संग्रह बढ़ाने,

अनुदानों पर फोकस और खर्चों के नियंत्रित प्रबंधन के जरिए नगर निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया गया है।अब यह बजट कार्यकारिणी की स्वीकृति के बाद आगामी वित्तीय वर्ष में लागू किया जाएगा।

आय के प्रमुख स्रोतों में बदलाव

नगर निगम के बजट में आय के प्रमुख मदों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं

संपत्ति कर में बढ़ोतरी

आवासीय एवं अनावासीय संपत्ति कर से आय को 320.00 करोड़ से बढ़ाकर 370.00 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है।

केडीए का कड़ा एक्शन: 950 वर्ग मीटर अवैध निर्माण सील

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर ।कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जोन-1बी क्षेत्र में करीब 950 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने निर्माणों को सील कर दिया। यह कार्रवाई उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल एवं सचिव अभय कुमार पाण्डेय के निर्देश पर विशेष कार्याधिकारी/उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई।प्रवर्तन टीम ने मगरवारा (उन्नाव) स्थित नेहरू बाग गेट नं. 3 में मो. शाहबुद्दीन, मो. एहतिशाम व अन्य द्वारा करीब 700 वर्ग मीटर में आरसीसी कॉलम पर किए गए निर्माण को सील किया।

जोन-1बी में दो स्थानों पर कार्रवाई, 4 अप्रैल को फिर चलेगा अभियान

वहीं सिंहपुर बाजार के पीछे (कानपुर) प्लॉट सं. 183 के सामने जितेंद्र सिंह व अन्य द्वारा करीब 250 वर्ग मीटर में जी+4 निर्माण को भी सील कर दिया गया। दोनों ही निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे थे।कार्रवाई के बाद दोनों परिसरों को संबंधित थाना बिठूर एवं उन्नाव पुलिस की अभिरक्षा में सौंपे जाने की प्रक्रिया जारी है। अभियान के दौरान अवर अभियंता हिमांशु बनवाल सहित प्रवर्तन टीम और पुलिस बल मौजूद रहा।

प्रवर्तन अधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि शुक्लागंज-उन्नाव क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग एवं व्यावसायिक निर्माणों का सर्वे कराया गया है, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 व 28 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि ग्राम गम्भीरपुर कछार में अवैध रूप से विकसित की जा रही 5 प्लाटिंग चिन्हित की गई हैं, जिनके विरुद्ध 4 अप्रैल 2026 को ध्वस्तीकरण/सीलिंग की कार्रवाई प्रस्तावित है।

केडीए ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे केवल स्वीकृत कॉलोनियों में ही प्लॉट खरीदें और नक्शा व ले-आउट की जांच के बाद ही निवेश करें। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

सम्पादकीय

मां-बाप की देखभाल के लिए कानूनी बाध्यता

वैसे तो यह किसी भी सभ्य समाज के लिये शर्मनाक है कि जन्म देकर पालन-पोषण करने वाले मां-बाप की जीवन की सांझ में बेकद्री की जाए। फिर गुजारे भत्ते के लिये कानून-प्रशासन से मांग करनी पड़े। लेकिन यह मौजूदा समय की हकीकत है कि ऐसे किस्से गाहे-बगाहे सुनने को मिलते हैं। सही मायनों में बुढ़ापा अपने आप में बड़ी चुनौती है, जब शरीर की क्षमताओं का ह्रास होने लगता है और आय के स्रोत लगभग खत्म होने लगते हैं। सेवानिवृत्ति की जमा-पूंजी बच्चों की पढ़ाई, शादी-ब्याह और मकान बनाने में खर्च हो जाती है। उन लोगों की स्थिति तो और दुखद हो जाती है जो निजी क्षेत्र या किसी प्राइवेट काम-धंधे में लगे रहते हैं। उन्हें तो पेंशन भी नहीं मिलती। वहीं धीरे-धीरे अक्षम होता शरीर उम्रदराज होने पर लगने वाली बीमारियों का घर बन जाता है। ऐसे स्थिति में अपने जब मां-बाप की देखभाल न करें तो यह एक सामाजिक अपराध ही कहा जाएगा। जाहिर है, जब खून के रिश्ते साथ न दें तो कानून ही अंतिम सहारा रह जाता है। इस दिशा में तेलंगाना विधानसभा में पारित तेलंगाना कर्मचारी जवाबदेही और माता-पिता सहायता निगरानी विधेयक 2026 पूरे देश के बुजुर्गों के लिये एक नई उम्मीद जगाता है। इस राज्य की विधानसभा ने बीते रविवार वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विधेयक पारित किया। निस्संदेह, देश में पहले से एक राष्ट्रीय कानून 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007' मौजूद है, लेकिन नये विधेयक का दायरा विस्तृत है। जो पहले कानून की कुछ विसंगतियों को दूर करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के नये विधेयक के दायरे में जनप्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। यह विधेयक जन प्रतिनिधियों, सरकारी व निजी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करना सुनिश्चित करता है।तेलंगाना विधानसभा में पारित यह विधेयक यकीनी बनाता है कि यदि बच्चे मां-बाप की देखभाल नहीं करते तो उनके वेतन से पंद्रह फीसदी या दस हजार रुपये, जो भी कम है, शिकायत मिलने पर माता-पिता को देय राशि के रूप में काटे जाएंगे। उल्लेखनीय है कि अपनी चल-अचल संपत्ति बेटे के नाम करने वाले मशहूर कारोबारी विजयपत सिंघानिया की बेदखली का एक मामला चर्चा में आया था। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा और देश में प्रभावी कानून बनाए जाने की चर्चा तेज हुई थी।

यह सुखद ही है कि तेलंगाना सरकार ने सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए यह पहल की। सरकार का कथन है कि समाज में नैतिक दायित्वों को बढ़ावा देना इस विधेयक का मकसद है। यदि बच्चे अपना दायित्व नहीं निभाते तो कानून के जरिये उन्हें इसके लिये बाध्य किया जा सकेगा। इस विधेयक में प्रावधान है कि बच्चों द्वारा मां-बाप का भरण-पोषण न करने पर वे जिला कलेक्टर के सामने आवेदन कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि यह कानून न केवल सरकारी कर्मचारियों पर बल्कि निजी क्षेत्र के कर्मियों, सांसदों, विधायकों, मनोनीत सदस्यों तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों पर भी लागू होगा।

निश्चित रूप से भारतीय परिवार परंपरा में सदियों से गरिमापूर्ण स्थान रखने वाले माता-पिता के सम्मान व जीवन-यापन सुनिश्चित करने की दिशा में यह विधेयक एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस विधेयक में जहां कलेक्टर को नामित प्राधिकारी बनाया गया है, वहीं माता-पिता को भी संपत्ति के बंटवारे की स्थिति व आय की स्पष्ट जानकारी देनी होगी। ऐसे मामलों में माता-पिता तथा कर्मचारी को सुनवाई का मौका मिलेगा।

यूपीएससी परीक्षा के जुनून से प्रभावित शैक्षिक वातावरण

के.एस तोमर

यूपीएससी परीक्षा के जुनून से प्रभावित शैक्षिक वातावरण देश में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के जुनून के कारण लाखों युवा मानसिक रूप से आहत हो रहे हैं और असफलता के दंश को भी झेल रहे हैं। वहीं इस परीक्षा के प्रति दीवानगी शैक्षणिक संस्कृति की...देश में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के जुनून के कारण लाखों युवा मानसिक रूप से आहत हो रहे हैं और असफलता के दंश को भी झेल रहे हैं। वहीं इस परीक्षा के प्रति दीवानगी शैक्षणिक संस्कृति की गंभीरता पर भी असर डाल रही है।हाल ही में, राष्ट्रीय राजधानी के एक अग्रणी महिला कॉलेज ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा-2025 में शीर्ष रैंक हासिल करने वाली अपनी दस पूर्व छात्राओं को सम्मानित किया। कॉलेज की प्रिंसिपल ने इन 'बदलाव के वाहकों' की सफलता गाथाओं का बखान किया, युवा छात्राओं को उनसे बातचीत करने अवसर मिला और उन 'गुरों' को सीखने का अवसर मिला, ताकि उन्हें भी इस अत्यंत प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए जरूरी महारत हासिल हो सके।

यह जोड़ने की जरूरत नहीं कि इस किस्म के आयोजन, जैसा कि कॉलेज की प्रिंसिपल ने सोचा होगा, वर्तमान छात्राओं में गर्व की भावना जगाने और उन्हें जीवन में अच्छा करने के लिए प्रेरित करने हेतु आवश्यक है। जहां मैं प्रिंसिपल और कॉलेज की इन दस पूर्व छात्राओं को बधाई देता हूं, वहीं मैं यह प्रार्थना करना नहीं भूलता कि ये 'सफल हस्तियां' अपने अहंकार पर काबू रख सकेंगी, विनम्र बनी रहेंगी,और अपने पदों से जुड़ी सत्ता और विशेषाधिकारों के मोहक जाल से खुद को दूर रखने का नैतिक साहस पा सकेंगी।हालांकि, ज्ञान की राजनीति और समाजशास्त्र में मेरी गहरी रुचि के कारण, परेशान करने वाला एक प्रश्न मुझे कचोटता रहता है। ऐसा क्यों है कि उदार कला एवं मानविकी संकाय के लिए जाना जाने वाला एक कॉलेज अपनी हैसियत सिद्ध करने के लिए यूपीएससी टॉपर्स को प्रदर्शित करने पर विवश है? मैं खुद से पूछता हूं क्या कॉलेज को अपनी इन पूर्व छात्राओं पर तब भी उतना ही गर्व होता, यदि उन्होंने जीवन का कोई बिल्कुल अलग मार्ग चुना होता– मसलन, छत्तीसगढ़ और झारखंड के आदिवासियों के बीच काम करने वाली एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में; या अपने छात्रों में आलोचनात्मक सोच के विकास की कोशिश करने वाली एक स्कूल शिक्षिका के रूप में; अथवा, इस संदर्भ में, अपने-अपने ज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाली किसी इतिहासकार/ राजनीतिक सिद्धांतकार/ मनोवैज्ञानिक के रूप में?इस बात को स्वीकार करें। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जिसने 'सफलता' और 'असफलता' की अपनी अलग अवधारणा गढ़ रखी है। कोई आश्चर्य नहीं कि शिक्षा का उद्देश्य अक्सर सफलता और असफलता को उपयोगिता के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। मसलन, यदि आप विज्ञान विषय चुनते हैं, तो आपको बार-बार यही कहा जाता है कि आपको डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है। या, इसी क्रम में, यदि आप मानविकी और सामाजिक विज्ञान चुनते हैं, तो आपका तब तक उद्धार नहीं हो सकता, जब तक आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करके आईएएस/ आईपीएस अधिकारी नहीं बन जाते! दरअसल, जिस तरह मध्यम-वर्गीय परिवार सफलता को लेकर प्रचलित इस सोच को आत्मसात कर लेते हैं, या फिर शिक्षा की यांत्रिक उपयोगिता ने युवाओं के लिए जीवन के अन्य रास्ते सोचना और उनके लिए कोशिश करना बेहद मुश्किल कर दिया है। इसलिए, समझा जा सकता है उदार कला एवं मानविकी विषय के लिए विख्यात कोई कॉलेज यूपीएससी टॉपर्स को अपना रोल मॉडल क्यों मानता है।तथापि, यह अहसास होना भी उतना ही ज़रूरी है कि सफलता को लेकर समाज द्वारा बनाई गई ऐसी सोच ने जिस चीज़ को जन्म दिया है, उसका नामकरण मैं 'यूपीएससी के जुनून की बीमारी' करना चाहूंगा–जिस तरह इसने 3000 करोड़ का भारी मुनाफा कमाने वाला 'कोचिंग उद्योग' खड़ा कर दिया है, अनगिनत युवा दिमागों की महत्त्वपूर्ण एवं रचनात्मक ऊर्जा को खत्म कर डाला है।

संकट अब ईरान की सीमाओं से बाहर फैला

अमेरिका-ईरान

अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार, यह संकट अब ईरान की सीमाओं से बाहर भी फैल चुका है। 19 मार्च तक अस्सी हजार से अधिक लोग देश छोड़ चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा लोग अफगानिस्तान पहुंचे हैं, जहां सत्तर हजार से अधिक लोगों ने शरण ली है।ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष ने पूरे पश्चिम एशिया को एक गहरे मानवीय संकट में धकेल दिया है। बीते एक महीने से लगातार हो रही बमबारी ने न केवल हजारों लोगों की जान ली है, बल्कि लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है।

ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 28 फरवरी से अब तक अमेरिका और इजराइल के हमलों में कम से कम 1937 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि चौबीस हजार आठ सौ से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़े इस बात की गंभीरता को दर्शाते हैं कि यह संघर्ष अब व्यापक मानवीय आपदा बन चुका है।इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक, इस संघर्ष के कारण अब तक बत्तीस लाख से अधिक लोग ईरान के भीतर ही विस्थापित हो चुके हैं। तेहरान, इस्फहान और केरमानशाह जैसे बड़े शहरों में सबसे ज्यादा हवाई और ड्रोन हमले हुए हैं, जिसके चलते लोग इन इलाकों को छोड़कर अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों और कैस्पियन सागर के पास के उत्तरी इलाकों की ओर जा रहे हैं। लेकिन हालात इतने खराब हैं कि सुरक्षित स्थान भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह गए हैं। कई जगहों पर लगातार हमलों के कारण लोगों के सामने यह दुविधा है कि वे अपने घरों में रहें या पलायन का जोखिम उठाएं।अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार, यह संकट अब ईरान की सीमाओं से बाहर भी फैल चुका है। 19 मार्च तक अस्सी हजार से अधिक लोग देश छोड़ चुके हैं। इनमें से

सबसे ज्यादा लोग अफगानिस्तान पहुंचे हैं, जहां सत्तर हजार से अधिक लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा पाकिस्तान, अजरबैजान, इराक और तुर्कमेनिस्तान में भी हजारों लोग पहुंचे हैं। यह पलायन इस बात का संकेत है कि लोगों को अब अपने देश में जीवन सुरक्षित नहीं लग रहा। डर, असुरक्षा और लगातार हो रहे हमलों ने आम नागरिकों को अपनी जान बचाने के लिए मजबूर कर दिया है।वहीं सीमाओं पर हालात और भी ज्यादा कठिन होते जा रहे हैं। ईरान से भागकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमाओं तक पहुंचने वाले लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राहत एजेंसियों के अनुसार, सीमाई चौकियों पर भारी भीड़, लंबी कतारें और सीमित संसाधनों के कारण लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी है।इसके अलावा, सुरक्षा स्थिति भी बेहद चिंताजनक बनी हुई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर लगातार झड़पें और गोलाबारी हो रही है, जिससे शरण लेने आए लोगों की जान भी खतरे में पड़ रही है। हाल के दिनों में सीमा क्षेत्रों में तोपखाने हमलों और सैन्य कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं, जिनमें आम नागरिक भी घायल हुए हैं। साथ ही कई बार सीमाएं अचानक बंद कर दी जाती हैं या सीमित समय के लिए खोली जाती हैं, जिससे हजारों लोग बीच रास्ते में फंस जाते हैं। कुछ मामलों में लोगों को जबरन वापस लौटाया जा रहा है, जबकि कई परिवार बिछड़ जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग एक युद्ध से बचकर भाग रहे हैं, वे अक्सर दूसरे संघर्ष और असुरक्षा के माहौल में पहुंच जाते हैं, जिससे उनकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती हैं। कुछ लोगों ने विदेशी सैन्य हस्तक्षेप का समर्थन भी किया है, जो इस बात को दर्शाता है कि देश के भीतर असंतोष कितना गहरा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, एक व्यक्ति ने बताया कि पिछले 47 वर्षों का दर्द अब असहनीय हो चुका है। वहीं एक अन्य व्यक्ति, जो सात साल जेल में रहा, उसने कहा कि जो पीड़ा उन्होंने झेली है, उसे समझ पाना आसान नहीं है। हालांकि, लोग डर और उम्मीद दोनों के बीच जी रहे हैं। वह अपनी जान और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, लेकिन साथ ही यह भी चाहते हैं कि यह संघर्ष किसी बड़े बदलाव की ओर ले जाए।

लंबी ट्रेनें, छोटा प्लेटफॉर्म, बिल्हौर में यात्रियों की सुरक्षा भगवान के सहारे

20 से अधिक बोगियों वाली ट्रेनों के कई डिब्बे प्लेटफॉर्म से बाहर रुकते

रिज़वान कुरैशी, स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर रेलवे स्टेशन पर छोटा प्लेटफॉर्म अब यात्रियों के लिए गंभीर खतरे का कारण बनता जा रहा है। यहां रुकने वाली ज्यादातर लंबी दूरी की ट्रेनों के कई डिब्बे प्लेटफॉर्म से बाहर ही खड़े रह जाते हैं, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रोजाना सैकड़ों यात्री जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं। स्थिति यह है कि 20 या उससे अधिक कोच वाली ट्रेनों में अक्सर पीछे या आगे के कई डिब्बे प्लेटफॉर्म की सीमा से बाहर रुक जाते हैं। ऐसे में यात्रियों को या तो प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों पर उतरना पड़ता है या फिर भागकर अपनी बोगी तक पहुंचना पड़ता है। कई बार यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते नजर आते हैं, जो बेहद खतरनाक है और कभी भी बड़े हादसे में बदल सकता है।

- जान जोखिम में डालकर चढ़ने-उतरने को मजबूर हैं यात्री
- सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को होती

स्थानीय लोगों और दैनिक यात्रियों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है, इसके बावजूद रेलवे प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सुबह-शाम के व्यस्त समय में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब भीड़ के बीच यात्रियों को अपनी बोगी तक पहुंचने के लिए धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं, बुजुर्गों और छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को होती है। उन्हें भारी सामान के साथ प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर चलना पड़ता है, जिससे गिरने और चोट लगने का खतरा बना रहता है। कई बार बुजुर्ग यात्रियों को दूसरों की मदद से किसी तरह ट्रेन में चढ़ाया जाता है। यात्रियों का कहना है कि प्लेटफॉर्म छोटा होने के कारण न केवल असुविधा हो रही है, बल्कि यह सीधे तौर पर सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। यात्रियों ने कहा प्लेटफॉर्म का विस्तार होना चाहिए , ताकि सभी बोगियां प्लेटफॉर्म के भीतर ही रुकें और यात्रियों को सुरक्षित तरीके से चढ़ने-उतरने की सुविधा मिल सके। हालत यह है कि 20 से अधिक बोगियों वाली ट्रेनों की कई बोगियां प्लेटफॉर्म से बाहर रुकने को मजबूर हैं।

बिल्हौर रेलवे स्टेशन।

इन ट्रेनों में सबसे ज्यादा परेशानी

14017	कालिंदी एक्सप्रेस
15084	उत्सर्ग एक्सप्रेस
10716	गोमती नगर एक्सप्रेस
19410	साबरमती एक्सप्रेस
14151	आंनद विहार दिल्ली
22443	बांद्रा एक्सप्रेस

प्लेटफॉर्म से आगे रुकी बोगियों में जान जोखिम में डालकर चढ़ते यात्री

यह मामला मेरी जानकारी में है। पूर्व में निरीक्षण किया जा चुका है। संबंधित कार्य को जल्द पूरा कराया जाएगा, ताकि लोगों को हो रही परेशानी दूर हो सके।
– संजीव शर्मा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, (इज्जतनगर मंडल)

आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। यह जनता से जुड़ा विषय है और यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में मैं रेल मंत्री जी से वार्ता कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराऊंगा।
– अशोक कुमार रावत, सांसद, मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र

हर दिन खतरे का सफर

बिल्हौर स्टेशन पर हर दिन सैकड़ों यात्री इस समस्या से जूझते हैं। प्लेटफॉर्म छोटा होने के कारण कई लोग पटरियों पर उतरकर अपनी बोगी तक पहुंचते हैं, जबकि कुछ यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये हालात किसी भी समय बड़े हादसे को जन्म दे सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अब तक इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

कब जागेगा रेलवे प्रशासन?

आखिर कब तक बिल्हौर स्टेशन पर यात्रियों की जान यूं ही जोखिम में डाली जाती रहेगी? वर्षों पुरानी इस समस्या का समाधान अब तक क्यों नहीं किया गया? क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही जिम्मेदारों की नींद खुलेगी, या फिर पहले ही यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी? या अधिकारियों को इसकी जानकारी ही नहीं है।

रोजाना 20 से अधिक बोगियों वाली ट्रेनें प्लेटफॉर्म से आगे रुकती

सड़क पर फैली निर्माण सामग्री राहगीर कैसे निकलें?

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। कस्बे से गुजर रहे लखनऊ-इटावा राजमार्ग पर ककवन रोड स्थित त्रिमूर्ति ट्रांसपोर्ट के सामने नाला निर्माण के चलते सड़क पर फैली सामग्री से आवागमन प्रभावित हो रहा है। राहगीरों को निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण सामग्री सड़क पर फैले होने से हादसे का खतरा बना हुआ है। वहीं दुकानदारों ने बताया कि इस वजह से ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है, जिससे व्यापार पर असर पड़ रहा है। दुकानदारों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं।

उनका आरोप है कि नाले में सरिया का जाल मानकों के अनुरूप नहीं डाला जा रहा है। नीचे डाली गई सीमेंट-गिट्टी की परत भी कई जगह से दरकने लगी है। लोगों ने प्रशासन से सड़क को जल्द साफ कराने और निर्माण कार्य की जांच कराने की मांग की है।

बिल्हौर के चार सितारों ने रचा यूपीपीसीएस में सुनहरा इतिहास

संघर्ष की राह से शिखर तक

- मातृत्व, गरीबी और असफलताओं से जूझते हुए हासिल की कामयाबी
- श्वेता 21वीं रैंक के साथ अव्वल, आयुष, वंशिका और अक्षांश भी चमके

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। कभी सीमित संसाधनों की कसौटी, कभी जिम्मेदारियों का बोझ और कभी असफलताओं की टीस–इन सबको पार करते हुए बिल्हौर के चार युवाओं ने सफलता की ऐसी कहानी लिखी है, जो पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीसीएस) 2024 का परिणाम जैसे ही घोषित हुआ, पूरे बिल्हौर में जश्न का माहौल बन गया।

इस सफलता के केंद्र में हैं शिवराजपुर की श्वेता वर्मा, जिन्होंने प्रदेश में 21वीं रैंक हासिल कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित कर दिया। लेकिन उनकी यह उपलब्धि सिर्फ एक रैंक नहीं, बल्कि संघर्ष, समर्पण और साहस की मिसाल है। बीटेक-एमटेक जैसी तकनीकी पढ़ाई के बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवा का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए लगातार मेहनत की। शादी और फिर मातृत्व की जिम्मेदारी–चार माह की बेटी की परवरिश–इन सबके बीच उन्होंने अपनी तैयारी को कभी नहीं छोड़ा। श्वेता की कहानी यह बताती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों, दृढ़ निश्चय के आगे सब झुक जाता है।

वहीं मरहमत नगर गांव के आयुष सिंह ने 194वीं रैंक हासिल कर यह साबित कर दिया कि संसाधनों की कमी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। एक किसान परिवार से आने वाले आयुष के सामने आर्थिक सीमाएं थीं, लेकिन उन्होंने मेहनत, अनुशासन और परिवार के सहयोग को अपनी ताकत बनाया। खेतों की पृष्ठभूमि से निकलकर प्रशासनिक सेवा तक का सफर तय करना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।

चौबेपुर की वंशिका सिंह की कहानी भी कम प्रेरणादायक नहीं है। दो बार असफलता मिलने के बाद भी उन्होंने अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई। तीसरे प्रयास में सफलता हासिल कर उन्होंने यह दिखा दिया कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सफलता की तैयारी होती है। बचपन से प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देखने वाली वंशिका ने लखनऊ में रहकर कड़ी मेहनत की और आखिरकार अपने सपने को साकार कर लिया।

इसी कड़ी में बिल्हौर के अक्षांश कटियार ने भी परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता ने यह संदेश दिया है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची, तो मंजिल दूर नहीं होती। परिणाम घोषित होते ही चारों सफल अभ्यर्थियों के घरों पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। गांव-गांव में मिठाइयां बांटी गईं और अभिभावकों के चेहरे गर्व से चमक उठे। हर कोई इन युवाओं की मेहनत और जज्बे की सराहना कर रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि इन चारों युवाओं ने न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए एक नई राह भी दिखाई है। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि संघर्ष चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हौसला बुलंद हो तो शिखर तक पहुंचना संभव है। यह चारों नाम अब सिर्फ सफल अभ्यर्थी नहीं, बल्कि बिल्हौर के सपनों की नई पहचान बन चुके हैं जहां संघर्ष हारता नहीं, बल्कि इतिहास रचता है।

श्वेता वर्मा

अक्षांश कटियार

वंशिका सिंह

आयुष सिंह

SWACHH SURVEKSHAN
#Mera Shahar, Meri Pehchan 2023

Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

श्री ए० के० शर्मा, नगर विकास मंत्री

श्रीमती प्रमिला पाण्डेय, महापौर

नगर निगम कानपुर

आइए! मिलकर स्वच्छता के प्रति कदम बढ़ाए, अपने कानपुर नगर को स्वच्छ बनाएं।

नगर की सफ़ाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में हमे चाहिए आपका सहयोग।
इसी क्रम में हम आपसे अपील करते है कि

- अपने घर के कूड़े को प्रथक-प्रथक करके नगर निगम द्वारा संचालित डोर टू डोर कूड़ा गाड़ी में ही डालें।
- सड़क पर कूड़ा न फेंके।
- आस पास साफ सफाई रखें, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें।
- प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें।
- Reduse, Reuse, Recycle की अवधारणा को अपने जीवन में आदत के रूप में ढालें।
- कानपुर नगर को साफ व स्वच्छ बनाने में कानपुर नगर निगम का सहयोग करें।

/KANPUR MUNICIPAL CORPORATION

श्री अर्पित उपाध्याय (आईएएस) नगर आयुक्त

जमीन के लिए बहन का कत्ल! भाइयों ने सिर कुचलकर ली जान

तलाक के बाद मायके में रह रही थी रेशमा, जमीन अपने नाम होने से भड़के भाई

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रिश्तों को तार-तार कर देने वाली यह खौफनाक घटना मूसानगर कस्बे से सामने आई है, जहां जमीनी लालच में भाइयों ने अपनी ही सगी बहन को मौत के घाट उतार दिया। घर के अंदर बंद कमरे में सिर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। चीखती रही बहन, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा।

सोमवार को फत्तेपुर निवासी रेशमा (40) का शव घर के कमरे में खून से लथपथ पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पहुंची बहन सीमा ने जब यह मंजर देखा तो उसके होश उड़ गए।

चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि रेशमा के पिता ने अपनी जमीन उसके नाम कर दी थी।

घटना स्थल पर जमा भीड़

इसी बात को लेकर उसके तीनों भाइयों बड़े, नियाज और छोटे से लंबे समय से विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट तक पहुंचा और रेशमा इस केस को जीत भी चुकी थी।

यही जीत उसकी मौत की वजह बन गई। करीब 15 साल पहले सिकंदरा निवासी अनवार से शादी हुई थी, लेकिन पति-पत्नी के बीच विवाद के चलते तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन था। दो बेटे आयान और ईशान पिता के साथ रह रहे हैं, जबकि रेशमा मायके में अकेली रह रही थी।

एक भाई हिरासत में

घटना की सूचना मिलते ही मूसानगर पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ भोगनीपुर संजय वर्मा ने मौके का निरीक्षण किया, जबकि फॉरेंसिक टीम ने अहम साक्ष्य जुटाए।थानाध्यक्ष रीना गौतम ने बताया कि बहन सीमा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुख्य आरोपी नियाजुद्दीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश जारी है। सीओ भोगनीपुर संजय वर्मा के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला जमीनी विवाद में हत्या का है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

जागा प्रशासन, लीकेज पाइप लाइन की मरम्मत कार्य शुरू

पटेल नगर में हर रोज सैकड़ों लीटर पानी सड़क पर बहकर बर्बाद हो रहा था

स्वराज इंडिया

पाइपलाइन लीकेज पर अफसर बेपरवाह, जलभराव से जनता बेहाल

हलचल खबर का असर

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लीकेज की मरम्मत करता कर्मचारी

कानपुर देहात। राजपुर नगर पंचायत के पटेल नगर में एक महीने से चली आ रही पेयजल पाइप लाइन लीकेज की समस्या आखिरकार सुलझने लगी है। स्वराज इंडिया में छपी खबर पर संबंधित विभाग हरकत में आया और मंगलवार को जल निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया।पटेल नगर के करीब 200 घरों में एमआरएफ सेंटर के पास बनी पानी की टंकी से जलापूर्ति की जाती है। करीब एक माह पूर्व इस्लाम, साबिर और नबीबक्श के घरों के सामने पाइप लाइन में लीकेज हो गया था। इससे हर रोज सैकड़ों लीटर पानी सड़क पर बहकर बर्बाद हो रहा था और आसपास जलभराव की स्थिति बनी हुई थी। स्थिति और गंभीर तब हो गई जब नाले के समीप पाइप लाइन लीकेज होने से दूषित पानी सप्लाई होने की आशंका बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं हो सका। स्वराज इंडिया अखबार ने सोमवार को इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसके बाद जल निगम और नगर पंचायत के अधिकारी सक्रिय हुए। मंगलवार को कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर पाइप लाइन की मरम्मत शुरू कर दी। जल निगम के जेई श्याम शंकर गुप्ता ने बताया कि लीकेज पाइप लाइन को ठीक करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जल्द ही आपूर्ति सामान्य हो जाएगी।

मुगल मार्ग पर अतिक्रमणकारियों पर कसा शिकंजा, 25 को नोटिस

» तीन दिन में खुद हटाने के दिए गए निर्देश फिर होगी कार्रवाई

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। मुगल मार्ग पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर राजपुर नगर पंचायत ने सख्ती शुरू कर दी है। सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर पंचायत ने 25 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी नीति त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार को नोटिस जारी किए गए। निर्धारित समय में अतिक्रमण न हटाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा और खर्च भी उनसे ही वसूला जाएगा। दुकानों के जरिए लंबे समय से अतिक्रमण किया जा रहा है। इससे सड़क की चौड़ाई कम हो गई है और आवागमन में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों को आए दिन जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ईओ ने स्पष्ट किया कि सड़क के मध्य से 35 फीट तक का अतिक्रमण हर हाल में हटाना होगा। निर्देशों का पालन न करने पर नगर पंचायत खुद कार्रवाई करेगी। नोटिस जारी होने के बाद अतिक्रमणकारियों में हलचल बढ़ गई है। कई लोग स्वयं ही अतिक्रमण हटाने में जुट गए हैं, जबकि अन्य लोग प्रशासन की अगली कार्रवाई को लेकर चिंतित हैं। नगर पंचायत की इस पहल से मुगल मार्ग पर यातायात व्यवस्था सुधारने की उम्मीद जताई जा रही है।

खून के कारोबार में हुई लापरवाही, 7 ब्लड बैंक सील

एआई जेनरेटेड प्रतीकात्मक फोटो

» एफएसडीए की छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे

» बिना डॉक्टर और रिकॉर्ड के चल रहा था काम

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) ने राजधानी के 25 ब्लड बैंकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें सात ब्लड बैंकों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। मरीजों की सेहत से खिलवाड़ करते पाए गए इन ब्लड बैंकों के संचालन पर तत्काल रोक लगा दी गई है और नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।

जांच के दौरान चैरिटेबल और सोसाइटी संचालित ब्लड बैंकों में कई गंभीर खामियां मिलीं।टीम को खाली ब्लड बैग की गुणवत्ता जांच का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जबकि रैपिड टेस्ट

के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई जा रही थी। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि कई जगहों पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे और यह तक दर्ज नहीं था कि खून किसने लिया और किसे जारी किया गया। ऐसे हालात में मरीजों को दिया जा रहा खून पूरी तरह असुरक्षित पाया गया।

एफएसडीए के सहायक आयुक्त ब्रजेश कुमार ने स्पष्ट कहा कि मरीजों की जान से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दोषी ब्लड बैंकों को सख्त सुधारात्मक कार्रवाई के बाद ही दोबारा संचालन की अनुमति दी जाएगी, जबकि अन्य ब्लड बैंकों की भी सघन जांच की जाएगी।इस कार्रवाई में विभागीय निगरानी की बड़ी कमी भी उजागर हुई है। वर्षों से मानकों की अनदेखी और रिकॉर्ड में लापरवाही जारी थी, जिससे पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब विभाग ने संकेत दिए हैं कि

पत्नी के अधिकार पर हाईकोर्ट सख्त पति को आय छिपाने की नहीं है छूट

कोर्ट ने कहा भरण-पोषण मामलों में आय-संपत्ति का खुलासा अनिवार्य

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ। घरेलू हिंसा और भरण-पोषण से जुड़े मामलों में पारदर्शिता को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट पति को उसकी आय और संपत्ति का पूरा ब्योरा देने के लिए बाध्य कर सकती है।

यह आदेश न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की एकल पीठ ने पत्नी और उसके नाबालिग पुत्र की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

अदालत ने निचली अदालत द्वारा पति की आय और संपत्ति का विवरण प्रस्तुत कराने की मांग खारिज करने के आदेश को निरस्त कर दिया और मामले पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए।

दरअसल, पत्नी ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और आर्थिक प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मुकदमा दायर किया था।

सुनवाई के दौरान उसने अदालत से पति के आयकर रिटर्न और अन्य वित्तीय दस्तावेज पेश कराने की मांग की थी, जिसे निचली अदालत ने 19 जनवरी 2026 को खारिज कर दिया था।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान आयकर विभाग से पति के पिछले दो वर्षों के रिटर्न मंगवाए, जिसमें उसकी वार्षिक आय लगभग 4.85 से 5.07 लाख रुपये पाई गई। जबकि निचली अदालत में उसने खुद को श्रमिक बताया था।

इस विरोधाभास पर अदालत ने गंभीर आपत्ति जताई।न्यायालय ने कहा कि रजनेश बनाम नेहा (2021 सुप्रीम कोर्ट केस) के फैसले के अनुसार, भरण-पोषण मामलों में पति की वास्तविक आय और संपत्ति का खुलासा जरूरी है और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज तलब किए जा सकते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि सही जानकारी के बिना न्याय संभव नहीं है।

डीजीपी नियुक्ति पर फिर घमासान 14 अफसरों का नया पैनल भेजा

रेणुका मिश्र के नाम से हटाया गया रिमार्क, सुनवाई से पहले बढ़ी हलचल; आईपीएस तबादलों ने खड़े किए सवाल

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार ने 1994 बैच तक के 14 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का दूसरा पैनल केंद्र को भेज दिया है।

इस बार सबसे ज्यादा चर्चा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रेणुका मिश्र को लेकर है, जिनके नाम के आगे पूर्व में दर्ज रिमार्क को हटा दिया गया है।डीजीपी चयन प्रक्रिया पहले से ही न्यायिक दायरे में है। मुख्य न्यायाधीश ने पिछली सुनवाई में मामले को दो सप्ताह के लिए स्थगित किया था,

जिसकी अवधि 1 अप्रैल को पूरी हो रही है। हालांकि अब तक पिछली सुनवाई का आदेश अपलोड नहीं होने से अगली सुनवाई के टलने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल अनिश्चितता बनी हुई है।

आईपीएस तबादलों से बढ़ी सियासी गर्मी

उधर, हाल ही में हुए आईपीएस अधिकारियों के तबादलों ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। जिन अधिकारियों को जिले से हटाकर साइड पोस्टिंग दी गई है। इनमें प्रबल प्रताप सिंह (महोबा), निपुण अग्रवाल (डीसीपी, लखनऊ) ,श्याम नारायण सिंह (एटा) ,राम नयन सिंह (बहराइच) जैसे नाम शामिल हैं।

इन तबादलों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि जिन अधिकारियों की कार्यशैली को सकारात्मक माना जा रहा था, उन्हें अचानक हटाया जाना कई सवाल खड़े कर रहा है।

खासकर निपुण अग्रवाल को उनकी ईमानदारी और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता रहा है।

जबकि प्रबल प्रताप सिंह को भी सरकार के प्रति समर्पित अधिकारी माना जाता रहा है।

चुनावी समय में फैसलों पर उठे सवाल

चुनावी माहौल के बीच इन प्रशासनिक फैसलों को लेकर विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों में चर्चा तेज हो गई है। सवाल यह उठ रहा है कि जिन अधिकारियों को लेकर सरकार की छवि पर सवाल उठते रहे, उनमें से किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई।कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे प्रशासनिक रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे चुनावी समीकरणों के लिहाज से लिया गया फैसला मान रहे हैं।

आगे की राह पर टिकी नजरें

अब सभी की नजरें कोर्ट की अगली सुनवाई और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। डीजीपी नियुक्ति और आईपीएस तबादलों से जुड़ा यह घटनाक्रम आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है।

विधवा बहू का हक मजबूत, ससुर से भी मांग सकती है गुजारा भत्ता

» हाईकोर्ट ने कहा पति की जिम्मेदारी मृत्यु के बाद भी जारी, कानून देता है सहारा

» शर्तें तय खुद की आय या संपत्ति न हो, पुनर्विवाह पर खत्म होगा अधिकार

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में हिंदू विधवा महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करते हुए स्पष्ट किया है कि वे अपने ससुर से भी गुजारा भत्ता मांग सकती हैं।अदालत ने कहा कि पति का अपनी पत्नी के भरण-पोषण का दायित्व उसकी मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता, और इसी आधार पर विधवा को ससुर से सहायता मांगने का अधिकार मिलता है।न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और सत्य वीर सिंह की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि भरण-पोषण का सिद्धांत

भारतीय कानून में स्थापित है।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 और 21 के तहत विधवा बहू को कुछ शर्तों के साथ ससुर या उनकी संपत्ति से भरण-पोषण मांगने का अधिकार प्राप्त है।अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि विधवा तभी ससुर से गुजारा भत्ता मांग सकती है, जब वह अपनी आय, पति की संपत्ति, माता-पिता या बच्चों के माध्यम से अपना पालन-पोषण करने में असमर्थ हो। साथ ही, यह जिम्मेदारी तभी लागू होगी जब ससुर के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध हों।कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि विधवा का पुनर्विवाह हो जाता है तो यह अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। फैसले में यह भी रेखांकित किया गया कि ऐसे मामलों में तथ्यों को साबित करने की जिम्मेदारी संबंधित पक्ष पर ही होती है और बिना ठोस साक्ष्य के किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता।यह फैसला घरेलू विवाद और भरण-पोषण से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी मार्गदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है।

कूड़ा जला कर हो रहा नाली निर्माण, जहरीले धुएं से लोग बेहाल

पालिका की लापरवाही से बढ़ा प्रदूषण संकट, शिकायतों के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई

»स्वराज इंडिया ब्यूरो

जौनपुर। मुंगराबादशाहपुर में पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली ने एक गंभीर जनस्वास्थ्य संकट खड़ा कर दिया है। जहां एक ओर सरकार खेतों में पराली जलाने पर सख्ती बरत रही है और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, वहीं नगर में स्वयं पालिका द्वारा कूड़ा-करकट जलाकर नाली निर्माण में उसका उपयोग किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाली निर्माण के दौरान बने गड्ढों को भरने के लिए मिट्टी के बजाय नगर से उठाए गए कूड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है और बाद में उसे जलवा दिया जाता है। इससे निकलने वाला जहरीला धुआं आसपास के निवासियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरा बन गया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है।

सालिक राम पटेल, अमर बहादुर पटेल, लालचंद यादव, संजय पटेल, महेंद्र कुमार और लालजी पटेल सहित कई स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह सब मिट्टी की लागत बचाने के उद्देश्य से जानबूझकर किया जा रहा है।

कूड़े की बदबू और धुएं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन समस्या के समाधान के बजाय अनदेखी कर रहा है। नागरिकों का कहना है कि उन्होंने सभासद और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस लापरवाही के चलते लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

उधर, भाकपा ने भी इस मुद्दे पर कड़ी आपत्ति जताई है। जिला मंत्री सालिक राम पटेल और अन्य पदाधिकारियों का कहना है कि इस समय खेतों में कटाई और मड़ाई का कार्य तेजी से चल रहा है।

ऐसे में कूड़े की आग से उठने वाली चिनगारियां तेज हवा या आंधी-तूफान के दौरान खेतों, छप्परों या घरों तक पहुंच सकती हैं, जिससे बड़ी आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो किसी बड़े हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता।

भाकपा नेताओं ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर पालिका द्वारा कूड़ा जलाने और उससे गड्ढे भरने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।

बीकापुर में बसपा ने ब्राह्मण चेहरे पर लगाया दांव

बसपा सुप्रीमो मायावती का मास्टरस्ट्रोक, राजा पाठक की एंट्री से सपा-बीजेपी की बढ़ी बेचैनी

समीर शाही स्वराज इंडिया

अयोध्या। अयोध्या की 274 बीकापुर विधानसभा सीट पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वच्छ छवि वाले राजा पाठक को आगे कर ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए ऐसा सियासी दांव चला है, जिसने पूरे इलाके की राजनीति में भूचाल ला दिया है। राजा पाठक को दिया गया यह आशीर्वाद सिर्फ एक एंट्री नहीं, बल्कि 2027 की रणनीति का साफ संकेत माना जा रहा है।

बीकापुर में ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोटरों का जटिल समीकरण हमेशा से चुनावी परिणाम तय करता रहा है। ऐसे में राजा पाठक की एंट्री बसपा के ÷सर्वजन हिताय÷ फॉर्मूले को फिर से जीवंत करती दिख रही है। खासतौर पर ब्राह्मण-दलित समीकरण को साधने की यह कोशिश सपा और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती बन गई है।

राजा पाठक ने बसपा में शामिल होते ही बहन मायावती के नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि ÷बसपा सरकार में कानून-व्यवस्था मजबूत रही, सड़कों और बुनियादी ढांचे का विकास हुआ और हर वर्ग को सम्मान मिला। यही वजह है कि जनता आज भी उस दौर को याद करती है।÷ राजनीतिक जानकारों की मानें तो बीकापुर में यह नया समीकरण अगर जमीन पर बैठ गया, तो 2027 में बसपा न सिर्फ मुकाबले को त्रिकोणीय बनाएगी, बल्कि सीधे-सीधे बाकी दलों की जीत की गणित भी बिगाड़ सकती है। बीकापुर की सियासत अब नए मोड़ पर है जहां स्वच्छ छवि, जातीय समीकरण और मायावती का सटीक दांव मिलकर चुनावी तस्वीर बदलने की पूरी तैयारी में है।

महिला कांस्टेबल की ईमानदारी, श्रद्धालु को वापस मिला खोया झुमका

» श्रद्धालुओं ने की पुलिस की कार्यशैली की सराहना

»स्वराज इंडिया ब्यूरो

अयोध्या। हनुमानगढ़ी मंदिर में तैनात महिला कांस्टेबल की ईमानदारी ने एक बार फिर पुलिस की सकारात्मक छवि पेश की है। सोमवार को लखनऊ निवासी श्रद्धालु रुचि सिंह परिवार के साथ दर्शन करने पहुंची थीं। इसी दौरान भीड़ में उनका करीब 3 ग्राम वजनी, लगभग 50 हजार रुपए कीमत का झुमका गिर गया।

ड्यूटी पर मौजूद कौशांबी जनपद की महिला कांस्टेबल सुष्मिता को यह झुमका मिला। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए इसकी सूचना हनुमानगढ़ी प्रभारी को दी। बाद में पहचान सुनिश्चित कर झुमका श्रद्धालु को वापस सौंप दिया गया।

अपना खोया आभूषण वापस पाकर रुचि सिंह भावुक हो गईं और महिला कांस्टेबल की ईमानदारी व संवेदनशीलता की सराहना करते हुए अयोध्या पुलिस का आभार व्यक्त किया।

दोस्तों संग नहाने गया युवक शारदा नदी में डूबा

»स्वराज इंडिया ब्यूरो

लखीमपुर खीरी। थाना क्षेत्र फूलबेहड़ के पचपेड़ी घाट पैंटून पुल के पास स्नान करने गये एक बालक की शारदा नदी में डूबकर मौत हो गई। सोमवार को मैनेहा खंभारखेड़ा निवासी विनीत कुमार पुत्र रविंद्र यादव उम्र 21वर्ष जो वाईडी कॉलेज का छात्र था। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ स्नान करने पचपेड़ी घाट गया था। जिसमें विनीत स्नान करते वक्त गहरे पानी में चला गया और वह डूबने लगा। विनीत को डूबता देख उसके अन्य साथियों ने उसको बचाने की कोशिश की मगर तब तक पानी की गहराई में विनीत गुम हो गया। जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से विनीत की तलाश की जा रही है। विनीत के पिता रविन्द्र यादव ने बताया कि विनीत एनसीसी का छात्र था व अपने कुछ अन्य सहपाठीयों के साथ स्नान करने आया था उसी समय यह हादसा हुआ। फूलबेहड़ थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि विनीत का कुछ पता नहीं चला है, एनडीआरएफ टीम को सूचना दे दी गई है।

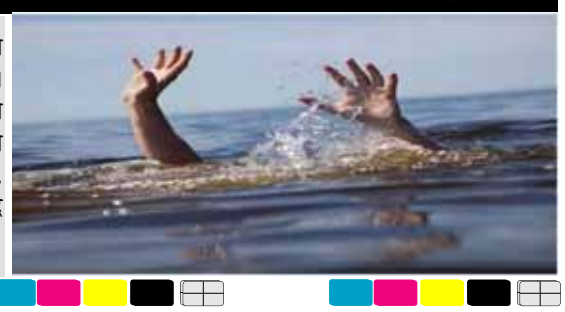

स्कूलों की मनमानी, वेंडरों का कमीशन खेल, बच्चों की पढ़ाई बनी महंगी 'डील'

अभिभावक बेहाल

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। एक अप्रैल से शुरू हो रहे नए शिक्षा सत्र से पहले अयोध्या में किताब-कॉपी और स्कूल ड्रेस का 'खेल' फिर बेनकाब हो गया है। बच्चों के चेहरों पर जहां नई क्लास की खुशी है, वहीं अभिभावकों के माथे पर महंगाई की गहरी लकीरें साफ दिख रही हैं।

रिकाबगंज, चौक, सोहावल, रुदौली, मवई, मिल्कीपुर और खंडासा के बाजारों की पड़ताल में सामने आया कि किताबें अभी तक पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन कीमतें पहले ही आसमान छू चुकी हैं। निजी स्कूलों में 40-50 फीसदी तक कमीशन के खेल की चर्चा आम है, जहां अभिभावकों को तय दुकानों से ही महंगे सेट खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। प्री-नर्सरी का सेट 2500-3000

» शिक्षा या सौदा? नए सत्र से पहले किताब-ड्रेस माफिया का शिकंजा

से बढ़कर 4500 तक पहुंच गया है, जबकि बड़ी कक्षाओं में खर्च 12 हजार तक जा रहा है। हर साल यूनिफॉर्म का रंग बदलकर नया बोझ डालना इस 'शिक्षा बाजार' की पुरानी चाल बन चुकी है।सबसे चौंकाने वाली बात स्कूल वेबसाइट पर रेट तक जारी नहीं कर रहे, ताकि अभिभावक विकल्प न तलाश सकें।एनसीईआरटी की सस्ती किताबों की जगह निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें थोप दी जाती हैं। जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई की बात तो करते हैं, लेकिन हालात हर साल जस के तस रहते हैं। सवाल सीधा है क्या शिक्षा अब अधिकार नहीं, बल्कि मुनाफे का कारोबार बन चुकी है?

अभिवावक दर्ज कराएं शिकायत

डीआईओएस डॉ. पवन कुमार तिवारी ने बताया कि किताबों के लिए प्रदेश स्तर से टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मई तक किताबें बाजार में उपलब्ध हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि जिन अभिभावकों को किताबों की उपलब्धता या कीमत को लेकर समस्या हो, वे शिकायत दर्ज कराएं, जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अयोध्या | **सरयू किनारे से सिविल सेवा तक**

अयोध्या के होनहारों ने यूपी पीसीएस में लिखी नई इबारत

» कटैया से कुमारगंज तक गूंजा परचम, गांव-गांव से निकले प्रशासन के नए चेहरे

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। यूपी पीसीएस परीक्षा में अयोध्या जनपद के होनहार अभ्यर्थियों ने शानदार सफलता हासिल कर जिले का मान बढ़ाया है। यह उपलब्धि बताती है कि अब प्रतिभा सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि गांव-गांव से निकलकर प्रशासनिक सेवा तक पहुंच रही है।इस सफलता सूची में अनामिका मिश्रा (डिप्टी कलेक्टर) के साथ कटैया भादी (धरौली) निवासी अनुपम तिवारी, कुमारगंज क्षेत्र के होनहार प्रणव पांडे, सोहावल के लहरपुर निवासी सत्यम तिवारी, मया ब्लॉक की शिक्षिका साक्षी पटेल, आनंद स्वरूप यादव, सोनम यादव और हाजीपुर बरसेंडी निवासी संजीत सिंह ने चयन पाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।इन सभी अभ्यर्थियों की सफलता संघर्ष, मेहनत और समर्पण की मिसाल है। सीमित संसाधनों के बावजूद इन्होंने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। इनकी कामयाबी अब अयोध्या के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है जहां आस्था के साथ अब प्रशासनिक सफलता की नई पहचान भी जुड़ती जा रही है।

नवप्रवेशी छात्रों का स्वागत, मेधावियों का सम्मान, गांव में शिक्षा का जश्न

वार्षिकोत्सव और प्रवेश समारोह में बच्चों ने बढ़ाया मान

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। प्राथमिक विद्यालय तकपुरा में वार्षिकोत्सव एवं प्रवेश उत्सव का भव्य आयोजन उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत करने के साथ मेधावी छात्रों को सम्मानित करना रहा।

मुख्य अतिथि एसआरपी अंबिकेश त्रिपाठी एवं विशिष्ट अतिथि एआरपी राहुल रिचा श्रीवास्तव की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रधानाध्यापक हेमंत कुमार शुक्ला ने विद्यालय की उपलब्धियों को साझा करते

हुए बताया कि इस वर्ष कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने नवोदय, विद्या ज्ञान,

अटल आवासीय एवं आश्रम पद्धति विद्यालयों में चयन पाकर गौरव बढ़ाया है।

चयनित विद्यार्थियों में अहेम, माही (नवोदय), खुशी वर्मा (विद्या ज्ञान व अटल आवासीय), आयुष विश्वकर्मा (अटल आवासीय), नितीश विश्वकर्मा (नवोदय) और

ऋषि विश्वकर्मा (आश्रम पद्धति) शामिल हैं। कार्यक्रम में शिक्षकों के योगदान की सराहना करते हुए अभिभावकों ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। आयोजन शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता और ग्रामीण प्रतिभा की ताकत का जीवंत उदाहरण बना।

अयोध्या में 7डी गैलरी का चमत्कार

17 मिनट में मिलेगा हनुमान गाथा का दिव्य अनुभव

» आस्था और आधुनिक तकनीक का संगम, स्पेशल इफेक्ट्स से जीवंत होंगे रामायण के दृश्य

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं को जल्द ही एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव मिलने जा रहा है। यहां तैयार अत्याधुनिक 7डी गैलरी में महज 17 मिनट में पवनपुत्र हनुमान की वीरता, भक्ति और पराक्रम की पूरी गाथा जीवंत रूप में दिखाई जाएगी।

इस गैलरी में एक बार में करीब 30 श्रद्धालु बैठकर स्पेशल इफेक्ट्स, ध्वनि और प्रकाश के साथ ऐसा अनुभव करेंगे मानो वे स्वयं रामायण के प्रसंगों के साक्षी हों। संजीवनी बूटी लाना, समुद्र लांघना और लंका दहन जैसे दृश्य विशेष तकनीक से प्रस्तुत किए जाएंगे। फ्रांस के तकनीकी विशेषज्ञों ने पांच दिन तक परीक्षण कर इसे त्रुटिरहित बनाया है। रामकथा संग्रहालय के निदेशक डॉ.

संजीव सिंह के अनुसार गैलरी पूरी तरह साउंडप्रूफ है और ट्रायल सफल रहा है। अब ट्रस्ट की मंजूरी मिलते ही इसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा।

होर्मुज पर 'नियंत्रण' की ईरानी चाल से वैश्विक संकट गहराया

टोल टैक्स, जहाजों पर रोक और खाड़ी देशों के दबाव के बीच अमेरिका की रणनीति दोराहे पर, तेल बाजार में उथल-पुथल की आशंका तेज

स्वराज इंडिया ब्यूरो

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान ने बड़ा और आक्रामक रणनीतिक कदम उठाया है। ईरान की संसद की सुरक्षा समिति ने इस अहम समुद्री मार्ग पर नियंत्रण और सख्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकारी मीडिया के मुताबिक, अब इस जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स लगाया जाएगा और उनकी आवाजाही के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे।

नई नीति के तहत सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, पर्यावरण संरक्षण के उपाय लागू करने और रियाल आधारित टोल सिस्टम लागू करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। सबसे अहम और विवादास्पद फैसला यह है कि अमेरिका और इजरायल के जहाजों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, साथ ही उन देशों के जहाजों को भी प्रतिबंधित किया जाएगा जो ईरान के विरोधी माने जाते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा असर डाल सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और एलएनजी का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में टोल टैक्स और प्रतिबंधों के चलते आपूर्ति बाधित होने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों में उछाल की आशंका बढ़ गई है। इसी बीच, डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की रणनीति में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका अब बिना होर्मुज को खुलवाए ही युद्ध समाप्त करने के विकल्प पर विचार कर रहा है, ताकि संघर्ष लंबा न खिंचे और कूटनीतिक दबाव के जरिए समाधान निकाला जा सके।

हालांकि, अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन ने ट्रंप पर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखने का दबाव बढ़ा दिया है। इन देशों का मानना है कि एक महीने के हमलों के बावजूद ईरान पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है और उस पर दबाव बनाए रखना जरूरी है। सूत्रों के अनुसार, खाड़ी देशों ने निजी स्तर पर संकेत दिया है कि जब तक ईरान के नेतृत्व या उसकी नीतियों में बड़ा बदलाव नहीं दिखता, तब तक सैन्य अभियान जारी रहना चाहिए। हालांकि ये देश सीधे युद्ध में शामिल नहीं हैं, लेकिन अपने यहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति दे रहे हैं।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर समर्थन जुटाना चुनौती बना हुआ है। अब तक 3,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर साफ दिखने लगा है। ऐसे में ट्रंप के सामने दोहरी चुनौती है एक ओर सहयोगियों का दबाव, तो दूसरी ओर जल्द समाधान निकालने की मजबूरी। कुल मिलाकर, होर्मुज पर ईरान की सख्ती, खाड़ी देशों का दबाव और अमेरिका की बदलती रणनीति ने पश्चिम एशिया को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां से आगे की हर चाल वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-राजनीति को गहराई से प्रभावित कर सकती है।

ट्रंप की दुविधा

डोनाल्ड ट्रंप के सामने दो विकल्प हैं। खाड़ी देशों के दबाव में आकर सैन्य अभियान तेज करना या कूटनीतिक समाधान निकालकर युद्ध खत्म करना। दोनों ही रास्तों में जोखिम है। युद्ध बढ़ाने से वैश्विक अस्थिरता बढ़ेगी, जबकि जल्दी समझौता करने पर राजनीतिक आलोचना झेलनी पड़ सकती है।

तेल बाजार पर असर

होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया का लगभग 20त्न तेल गुजरता है। ऐसे में किसी भी तरह की बाधा से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा–पेट्रोल-डीजल महंगा हो सकता है और महंगाई बढ़ सकती है।

ईरान की रणनीति क्या है?

ईरान इस कदम के जरिए सैन्य दबाव के साथ आर्थिक दबाव भी बनाना चाहता है। टोल टैक्स और प्रतिबंधों के जरिए वह वैश्विक शक्तियों को यह संदेश दे रहा है कि यदि उस पर दबाव बढ़ाया गया तो वह वैश्विक सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकता है।

- होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का नियंत्रण सख्त
- जहाजों पर टोल टैक्स लागू करने की योजना
- अमेरिका और इजरायल के जहाजों पर पूर्ण प्रतिबंध
- वैश्विक तेल आपूर्ति पर संकट के संकेत
- खाड़ी देशों का अमेरिका पर युद्ध जारी रखने का दबाव
- अमेरिका के भीतर युद्ध को लेकर समर्थन कमजोर

सीएम योगी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप, कई जिलों में मुकदमे दर्ज होने के बाद कार्रवाई

मौलाना अब्दुल्ला सलीम गिरफ्तार, यूपी STF ने बिहार से पकड़ा

स्वराज इंडिया ब्यूरो

लखनऊ/पूर्णिया। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी मौलाना अब्दुल्ला सलीम को बिहार के पूर्णिया जिले से गिरफ्तार किया है। कार्रवाई सोमवार देर रात की गई, जिसमें स्थानीय बिहार पुलिस का भी सहयोग लिया गया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी को पूर्णिया से हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है और उसे आगे की पूछताछ के लिए उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। मामले को लेकर पहले से ही राज्य के कई जिलों में मुकदमे दर्ज थे, जिसके बाद एसटीएफ को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।

कई जिलों में दर्ज हुए मुकदमे

विवाद बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश के बहराइच, बलरामपुर समेत कई जिलों में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने शिकायतों के आधार पर धार्मिक भावनाएं आहत करने, आपत्तिजनक टिप्पणी करने और शांति व्यवस्था प्रभावित करने से जुड़ी धाराओं में मुकदमा कायम किया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यूपी एसटीएफ को आरोपी की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर पूर्णिया में दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही वायरल वीडियो की सत्यता, उसके स्रोत और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। प्रशासन ने मामले को संवेदनशील मानते हुए सभी जिलों में सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की अफवाह या अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वायरल वीडियो से शुरू हुआ विवाद: जानकारी के मुताबिक, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें मौलाना पर मुख्यमंत्री की मां और गौमाता के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने का आरोप है। वीडियो सामने आने के बाद विभिन्न संगठनों और लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई, जिससे मामला तेजी से बढ़ा।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार RNI No.:** UPHIN/2023/86769 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com